Indian Journal of
Modern Research and Reviews
This Journal is a member of the 'Committee on Publication Ethics'
Online ISSN:2584-184X

Review Paper

डिजिटल मीडिया और आदिवासी महिला सशक्तिकरण: समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में एक सैद्धांतिक पुनर्व्याख्या

विजय सिंह [1*], डॉ. हितेंद्र सिंह राठौड़ [2]
[1] शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, बनस्थली विद्यापीठ, निवाई, टोंक राजस्थान, भारत
[2] एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, बनस्थली विद्यापीठ, निवाई, टोंक राजस्थान, भारत

Corresponding Author: *विजय सिंह
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20591567

सारांश

डिजिटल मीडिया ने सूचना, शिक्षा, संचार और आर्थिक अवसरों तक पहुँच को बढ़ाकर सामाजिक परिवर्तन की नई संभावनाएँ उत्पन्न की हैं। आदिवासी महिलाएँ, जो लैंगिक, आर्थिक और सामाजिक वंचनाओं का सामना करती हैं, डिजिटल माध्यमों के जरिए सशक्तिकरण के नए अवसर प्राप्त कर रही हैं। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य डिजिटल मीडिया और आदिवासी महिला सशक्तिकरण के संबंध का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण करना तथा इसकी सैद्धांतिक पुनर्व्याख्या प्रस्तुत करना है। यह अध्ययन द्वितीयक स्रोतों एवं प्रमुख समाजशास्त्रीय सिद्धांतों—नेटवर्क समाज सिद्धांत, सामाजिक पूँजी सिद्धांत, क्षमता दृष्टिकोण, नारीवादी सिद्धांत तथा इंटरसेक्शनैलिटी पर आधारित है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि डिजिटल मीडिया सामाजिक पूँजी निर्माण, सांस्कृतिक पहचान, राजनीतिक सहभागिता तथा निर्णय क्षमता को बढ़ाने में सहायक है, किंतु डिजिटल विभाजन, डिजिटल पितृसत्ता और साइबर चुनौतियाँ इसकी प्रभावशीलता को सीमित करती हैं। अध्ययन के आधार पर आदिवासी डिजिटल एजेंसी रूपरेखा *(TDAF)* प्रस्तावित किया गया है, जो डिजिटल पहुँच से बहुआयामी सशक्तिकरण तक की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। यह शोध आदिवासी महिला सशक्तिकरण को समझने के लिए एक समग्र समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्रदान करता है।

Manuscript Info.

- ✓ **ISSN No:** 2584- 184X
- ✓ **Received:** 05-04-2025
- ✓ **Accepted:** 28-05-2025
- ✓ **Published:** 30-05-2025
- ✓ **MRR:3(5):**2025;87-92
- ✓ **©2025, All Rights Reserved.**
- ✓ **Peer Review Process:** Yes
- ✓ **Plagiarism Checked:** Yes

How To Cite

विजय सिंह, डॉ. हितेंद्र सिंह राठौड़. डिजिटल मीडिया और आदिवासी महिला सशक्तिकरण: समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में एक सैद्धांतिक पुनर्व्याख्या. Indian J Mod Res Rev. 2025;3(5):87-92.

मूल शब्द: डिजिटल मीडिया, आदिवासी महिला, सशक्तिकरण, डिजिटल विभाजन, सामाजिक पूँजी, डिजिटल एजेंसी।

परिचय

इक्कीसवीं सदी को सूचना, संचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी की सदी कहा जाता है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल संचार ने मानव जीवन की संरचना में अभूतपूर्व परिवर्तन किए हैं। इन तकनीकों ने न केवल संचार के स्वरूप को बदला है, बल्कि ज्ञान उत्पादन, राजनीतिक भागीदारी, आर्थिक गतिविधियों तथा सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के नए अवसर भी निर्मित किए हैं। मैनुअल कास्टेल्स (2010) ने इस परिवर्तन को "नेटवर्क समाज" की संज्ञा दी, जहाँ शक्ति, सूचना और संसाधनों का प्रवाह डिजिटल नेटवर्कों के माध्यम से संचालित होता है।

भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, भारतनेट परियोजना, कॉमन सर्विस सेंटर, डिजिटल भुगतान प्रणाली तथा स्मार्टफोन क्रांति ने डिजिटल समावेशन की दिशा में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर भी, डिजिटल विकास की यह प्रक्रिया सामाजिक रूप से असमान रही है। ग्रामीण-शहरी अंतर, लैंगिक विषमता, आर्थिक असमानता तथा जातीय-जनजातीय विभाजन डिजिटल पहुँच को प्रभावित करते हैं। विशेष रूप

© 2025 विजय सिंह, डॉ. हितेंद्र सिंह राठौड़. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

से आदिवासी समुदायों में डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता और उपयोग का स्तर अपेक्षाकृत कम पाया गया है।

आदिवासी महिलाएँ भारतीय समाज के सबसे अधिक हाशिए पर स्थित समूहों में से एक हैं। वे केवल महिला होने के कारण ही नहीं, बल्कि जनजातीय पहचान, भौगोलिक अलगाव, सीमित शैक्षिक अवसर, आर्थिक अभाव तथा सांस्कृतिक उपेक्षा के कारण भी बहुआयामी वंचना का सामना करती हैं। इसलिए उनका सशक्तिकरण भारतीय लोकतंत्र और समावेशी विकास की एक केंद्रीय चुनौती है।

समकालीन समय में डिजिटल मीडिया आदिवासी महिलाओं के लिए नई संभावनाएँ प्रस्तुत कर रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ई-गवर्नेंस सेवाएँ, डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन उद्यमिता और डिजिटल वित्तीय प्रणालियाँ उन्हें सूचना, संसाधन और नेटवर्क तक पहुँच प्रदान कर रही हैं। अनेक क्षेत्रों में आदिवासी महिलाएँ डिजिटल मंचों का उपयोग कर स्थानीय उत्पादों का विपणन कर रही हैं, सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर रही हैं तथा सामुदायिक नेतृत्व की भूमिका निभा रही हैं।

फिर भी यह प्रश्न बना हुआ है कि क्या डिजिटल पहुँच वास्तव में सशक्तिकरण में परिवर्तित हो रही है? क्या डिजिटल मीडिया पारंपरिक शक्ति संबंधों को चुनौती दे रहा है या केवल उन्हें नए रूप में पुनर्स्थापित कर रहा है? क्या डिजिटल समावेशन सामाजिक न्याय सुनिश्चित कर सकता है? यही प्रश्न इस शोध-पत्र की केंद्रीय चिंता है।

शोध उद्देश्य

इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. डिजिटल मीडिया और आदिवासी महिला सशक्तिकरण के अंतर्संबंध का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना।
2. डिजिटल सशक्तिकरण की अवधारणा को प्रमुख समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के माध्यम से पुनर्व्याख्यायित करना।
3. डिजिटल मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना।
4. आदिवासी महिला सशक्तिकरण के लिए एक नवीन सैद्धांतिक मॉडल प्रस्तुत करना।

शोध पद्धति

यह अध्ययन गुणात्मक तथा अवधारणात्मक प्रकृति का है। इसमें द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है, जिनमें शामिल हैं—

- समकालीन शोध लेख
- पुस्तकें
- नीति दस्तावेज
- अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टें
- महिला एवं जनजातीय अध्ययन से संबंधित साहित्य

अध्ययन में विषयवस्तु विश्लेषण तथा आलोचनात्मक विमर्श विश्लेषण की पद्धति अपनाई गई है।

सैद्धांतिक रूपरेखा

डिजिटल मीडिया और आदिवासी महिला सशक्तिकरण के संबंध को समझने के लिए यह अध्ययन विभिन्न समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का उपयोग करता है। ये सिद्धांत डिजिटल तकनीक, सामाजिक संरचना, शक्ति संबंधों और सशक्तिकरण की प्रक्रिया को व्याख्यायित करने में सहायक हैं।

नेटवर्क समाज सिद्धांत : मैनुअल कास्टेल्स (Castells, 2010) के अनुसार आधुनिक समाज सूचना और संचार नेटवर्कों पर आधारित है। डिजिटल मीडिया आदिवासी महिलाओं को स्थानीय सीमाओं से बाहर निकालकर व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नेटवर्कों से जोड़ता है। इससे सूचना, संसाधनों और अवसरों तक उनकी पहुँच बढ़ती है।

सामाजिक पूँजी सिद्धांत : पियरे बोरदियू (Bourdieu, 1986) के अनुसार सामाजिक संबंध और नेटवर्क एक महत्वपूर्ण पूँजी हैं। डिजिटल मीडिया आदिवासी महिलाओं को नए सामाजिक नेटवर्क, संस्थागत संपर्क और सामुदायिक सहयोग विकसित करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे उनकी सामाजिक पूँजी और सशक्तिकरण में वृद्धि होती है।

क्षमता दृष्टिकोण : अमर्त्य सेन (Sen, 1999) के अनुसार विकास का अर्थ केवल आय वृद्धि नहीं, बल्कि व्यक्तियों की क्षमताओं और विकल्पों का विस्तार है। डिजिटल मीडिया शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय सेवाओं और सरकारी योजनाओं तक पहुँच प्रदान कर आदिवासी महिलाओं की क्षमताओं का विकास करता है।

नारीवादी सिद्धांत : नारीवादी दृष्टिकोण यह मानता है कि तकनीक और समाज दोनों लैंगिक शक्ति संबंधों से प्रभावित होते हैं। डिजिटल मीडिया महिलाओं को अभिव्यक्ति, संगठन और अधिकारों के प्रति जागरूकता का मंच प्रदान करता है, जिससे वे पितृसत्तात्मक संरचनाओं को चुनौती दे सकती हैं।

इंटरसेक्शनैलिटी सिद्धांत : किम्बर्ले क्रेंशॉ (Crenshaw, 1989) के अनुसार व्यक्ति की पहचान अनेक सामाजिक कारकों—जैसे लिंग, जातीयता, वर्ग और क्षेत्र—के अंतर्संबंध से निर्मित होती है। आदिवासी महिलाएँ बहुआयामी वंचनाओं का सामना करती हैं; इसलिए उनके डिजिटल सशक्तिकरण को केवल लैंगिक दृष्टि से नहीं, बल्कि जनजातीय, आर्थिक और सामाजिक संदर्भों में भी समझना आवश्यक है।

उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर यह अध्ययन मानता है कि डिजिटल मीडिया केवल तकनीकी साधन नहीं, बल्कि सामाजिक पूँजी निर्माण, क्षमता विकास, पहचान निर्माण और शक्ति संबंधों के पुनर्गठन का माध्यम है। इसलिए आदिवासी महिला सशक्तिकरण को एक बहुआयामी सामाजिक प्रक्रिया के रूप में समझा जाना चाहिए।

डिजिटल मीडिया और आदिवासी महिला सशक्तिकरण: समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डिजिटल मीडिया ने समकालीन समाज में संचार, सूचना आदान-प्रदान और सामाजिक सहभागिता की प्रकृति को व्यापक रूप से परिवर्तित किया है। आदिवासी महिलाओं के संदर्भ में इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यह उन्हें पारंपरिक सामाजिक सीमाओं से बाहर निकलकर ज्ञान, संसाधनों और अवसरों तक पहुँच प्रदान करता है।

© 2025 विजय सिंह, डॉ. हितेंद्र सिंह राठौड़. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से डिजिटल मीडिया केवल एक तकनीकी साधन नहीं, बल्कि सामाजिक संबंधों, शक्ति संरचनाओं और पहचान निर्माण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण माध्यम है। यह आदिवासी महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सशक्तिकरण में बहुआयामी भूमिका निभाता है।

सूचना एवं ज्ञान तक पहुँच का विस्तार : सूचना आधुनिक समाज में शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। डिजिटल मीडिया के माध्यम से आदिवासी महिलाएँ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार तथा सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। इससे उनकी जागरूकता और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। ज्ञान तक बढ़ी हुई पहुँच उन्हें सामाजिक रूप से अधिक सक्षम बनाती है तथा विकास प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी को सुदृढ़ करती है।

सामाजिक पूँजी और नेटवर्क निर्माण : डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म आदिवासी महिलाओं को स्थानीय समुदायों से परे व्यापक सामाजिक नेटवर्कों से जोड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप समूह और ऑनलाइन समुदायों के माध्यम से वे अनुभवों का आदान-प्रदान, सहयोग और सामूहिक संगठन विकसित कर सकती हैं। यह प्रक्रिया सामाजिक पूँजी (Social Capital) के निर्माण में सहायक होती है, जो उनके सामाजिक सशक्तिकरण का आधार बनती है।

आर्थिक सशक्तिकरण और डिजिटल उद्यमिता : डिजिटल मीडिया ने आर्थिक गतिविधियों के नए अवसरों को जन्म दिया है। आदिवासी महिलाएँ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल भुगतान प्रणालियों के माध्यम से अपने उत्पादों और सेवाओं को व्यापक बाजार तक पहुँचा सकती हैं। इससे उनकी आय में वृद्धि, आर्थिक आत्मनिर्भरता और वित्तीय निर्णय क्षमता का विकास होता है। डिजिटल उद्यमिता उन्हें पारंपरिक आर्थिक निर्भरता से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करती है।

सांस्कृतिक पहचान और प्रतिनिधित्व : डिजिटल मीडिया आदिवासी महिलाओं को अपनी सांस्कृतिक विरासत, लोक कला, लोकगीत, परंपराओं और भाषाई पहचान को संरक्षित एवं प्रसारित करने का मंच प्रदान करता है। इससे न केवल उनकी सांस्कृतिक पहचान को मान्यता मिलती है, बल्कि मुख्यधारा समाज में आदिवासी संस्कृति की दृश्यता भी बढ़ती है। यह प्रक्रिया सांस्कृतिक सशक्तिकरण और आत्मगौरव की भावना को मजबूत करती है।

राजनीतिक सहभागिता और नागरिक चेतना : डिजिटल मीडिया लोकतांत्रिक सहभागिता का एक प्रभावी माध्यम बन गया है। इसके माध्यम से आदिवासी महिलाएँ सरकारी योजनाओं, अधिकारों और नीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करती हैं तथा सार्वजनिक मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठा सकती हैं। ऑनलाइन मंच उन्हें स्थानीय शासन, सामाजिक आंदोलनों और सामुदायिक निर्णय प्रक्रियाओं में भागीदारी का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे उनकी राजनीतिक एजेंसी का विस्तार होता है।

डिजिटल चुनौतियाँ और संरचनात्मक बाधाएँ : यद्यपि डिजिटल मीडिया सशक्तिकरण के अनेक अवसर प्रदान करता है, फिर भी आदिवासी महिलाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। डिजिटल विभाजन, इंटरनेट सुविधाओं की कमी, सीमित डिजिटल साक्षरता, साइबर हिंसा, भाषाई बाधाएँ तथा पितृसत्तात्मक नियंत्रण उनकी डिजिटल भागीदारी को प्रभावित करते हैं। इसलिए डिजिटल सशक्तिकरण को केवल तकनीकी उपलब्धता के आधार पर नहीं समझा जा सकता, बल्कि इसे व्यापक सामाजिक और संरचनात्मक संदर्भों में देखना आवश्यक है।

आलोचनात्मक विमर्श

डिजिटल मीडिया को सामान्यतः महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समावेशन के प्रभावी माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, किंतु इसका प्रभाव सर्वत्र समान और सकारात्मक नहीं है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से डिजिटल तकनीक स्वयं तटस्थ नहीं होती, बल्कि वह मौजूदा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति-संबंधों से प्रभावित होती है। इसलिए आदिवासी महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में डिजिटल मीडिया का आलोचनात्मक विश्लेषण आवश्यक है।
डिजिटल विभाजन : यद्यपि डिजिटल अवसंरचना का विस्तार हुआ है, फिर भी आदिवासी क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन उपलब्धता तथा डिजिटल साक्षरता की कमी बनी हुई है। डिजिटल संसाधनों तक असमान पहुँच आदिवासी महिलाओं को डिजिटल विकास की मुख्यधारा से दूर रखती है। इस प्रकार डिजिटल मीडिया कभी-कभी सामाजिक असमानताओं को कम करने के बजाय उन्हें और गहरा भी कर सकता है।

डिजिटल पितृसत्ता : कई आदिवासी और ग्रामीण समुदायों में महिलाओं के मोबाइल फोन उपयोग पर पारिवारिक एवं सामाजिक नियंत्रण देखा जाता है। अनेक मामलों में डिजिटल उपकरणों का स्वामित्व पुरुषों के पास होता है तथा महिलाओं की ऑनलाइन गतिविधियाँ निगरानी के दायरे में रहती हैं। परिणामस्वरूप डिजिटल पहुँच होने के बावजूद महिलाओं की स्वायत्तता सीमित रह सकती है।
साइबर हिंसा और ऑनलाइन उत्पीड़न : डिजिटल मंच महिलाओं के लिए अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन साथ ही साइबर बुलिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न, ट्रोलिंग और लैंगिक हिंसा के जोखिम भी बढ़ाते हैं। ऐसे अनुभव महिलाओं की डिजिटल भागीदारी और आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकते हैं।

सांस्कृतिक और भाषाई बहिष्करण : अधिकांश डिजिटल सामग्री प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध होती है, जबकि अनेक आदिवासी भाषाओं और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का डिजिटल प्रतिनिधित्व सीमित है। इससे आदिवासी महिलाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रभावी उपयोग कठिन हो जाता है तथा उनकी सांस्कृतिक पहचान हाशिए पर चली जाती है।

डेटा और शक्ति का प्रश्न : डिजिटल प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं के डेटा को एकत्रित और नियंत्रित करते हैं। आदिवासी समुदायों की डिजिटल भागीदारी बढ़ने के साथ उनके व्यक्तिगत एवं सामुदायिक

© 2025 विजय सिंह, डॉ. हितेंद्र सिंह राठौड़. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

डेटा के दुरुपयोग की आशंकाएँ भी बढ़ती हैं। यह स्थिति "डेटा उपनिवेशवाद" (Data Colonialism) की अवधारणा से जुड़ी हुई है, जहाँ वैश्विक डिजिटल कंपनियाँ स्थानीय समुदायों के डेटा से लाभ अर्जित करती हैं।

सशक्तिकरण बनाम सहभागिता : डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय उपस्थिति को हमेशा वास्तविक सशक्तिकरण नहीं माना जा सकता। सोशल मीडिया पर सहभागिता तभी सार्थक है जब वह महिलाओं की निर्णय क्षमता, संसाधनों पर नियंत्रण, सामाजिक प्रतिष्ठा और राजनीतिक भागीदारी में वास्तविक वृद्धि करे। केवल तकनीकी पहुँच या ऑनलाइन उपस्थिति को सशक्तिकरण का पर्याय नहीं माना जा सकता।

प्रस्तावित सैद्धांतिक मॉडल : आदिवासी डिजिटल एजेंसी रूपरेखा (Tribal Digital Agency Framework - TDAF)

वर्तमान अध्ययन के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों तथा आलोचनात्मक विश्लेषण के आधार पर "Tribal Digital Agency Framework (TDAF)" प्रस्तावित किया गया है। यह मॉडल डिजिटल मीडिया और आदिवासी महिला सशक्तिकरण के बीच संबंध को एक क्रमिक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में व्याख्यायित करता है।

मॉडल का स्वरूप

डिजिटल पहुँच (Digital Access)
↓
डिजिटल साक्षरता (Digital Literacy)
↓
डिजिटल सहभागिता (Digital Participation)
↓
सामाजिक पूँजी निर्माण (Social Capital Formation)
↓
सांस्कृतिक मान्यता एवं पहचान (Cultural Recognition and Identity)
↓
एजेंसी एवं निर्णय क्षमता (Agency and Decision-Making Power)
↓
बहुआयामी सशक्तिकरण (Multidimensional Empowerment)

डिजिटल पहुँच : सशक्तिकरण की प्रक्रिया का प्रथम चरण डिजिटल संसाधनों तक पहुँच है। इसमें स्मार्टफोन, इंटरनेट, डिजिटल उपकरण तथा संचार अवसंरचना की उपलब्धता शामिल है। यदि आदिवासी महिलाओं के पास डिजिटल संसाधनों तक पहुँच नहीं होगी, तो वे डिजिटल अवसरों का लाभ नहीं उठा सकेंगी।

डिजिटल साक्षरता : केवल उपकरण उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं है। डिजिटल तकनीक का प्रभावी उपयोग करने के लिए तकनीकी ज्ञान और कौशल आवश्यक हैं। डिजिटल साक्षरता महिलाओं को ऑनलाइन जानकारी खोजने, डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने तथा साइबर जोखिमों से बचने में सक्षम बनाती है।

डिजिटल सहभागिता : डिजिटल साक्षरता प्राप्त होने के बाद महिलाएँ सोशल मीडिया, ई-गवर्नेंस, डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन व्यवसाय तथा सामुदायिक नेटवर्कों में सक्रिय भागीदारी करने लगती हैं। यह सहभागिता उन्हें व्यापक सामाजिक प्रक्रियाओं से जोड़ती है।

सामाजिक पूँजी निर्माण : डिजिटल सहभागिता के माध्यम से नए सामाजिक संबंध, नेटवर्क और सहयोग के अवसर विकसित होते हैं। बोरदियू के सामाजिक पूँजी सिद्धांत के अनुसार ये नेटवर्क संसाधनों और अवसरों तक पहुँच को बढ़ाते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों, सरकारी संस्थाओं और बाजारों से जोड़ते हैं।

सांस्कृतिक मान्यता एवं पहचान : डिजिटल मीडिया आदिवासी महिलाओं को अपनी भाषा, संस्कृति, कला और परंपराओं को अभिव्यक्त करने का मंच प्रदान करता है। इससे उनकी सांस्कृतिक पहचान को मान्यता मिलती है और सांस्कृतिक आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।

एजेंसी एवं निर्णय क्षमता : सामाजिक पूँजी और सांस्कृतिक मान्यता महिलाओं के आत्मविश्वास, स्वायत्तता और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती है। वे व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामुदायिक स्तर पर अधिक सक्रिय भूमिका निभाने लगती हैं। यही अवस्था "डिजिटल एजेंसी" का निर्माण करती है।

बहुआयामी सशक्तिकरण : अंतिम चरण में डिजिटल एजेंसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण में परिवर्तित होती है। महिलाएँ आय अर्जित करने, शिक्षा प्राप्त करने, राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने में सक्षम बनती हैं।

मॉडल की विशेषताएँ :

- यह मॉडल सशक्तिकरण को एक प्रक्रिया के रूप में देखता है, न कि केवल परिणाम के रूप में।
- यह तकनीकी कारकों के साथ-साथ सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों को भी महत्व देता है।
- यह नेटवर्क समाज सिद्धांत, सामाजिक पूँजी सिद्धांत, क्षमता दृष्टिकोण और इंटरसेक्शनैलिटी सिद्धांत का समन्वित उपयोग करता है।
- यह आदिवासी महिलाओं की विशिष्ट सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखता है।
- यह दर्शाता है कि डिजिटल पहुँच तभी वास्तविक सशक्तिकरण में परिवर्तित होती है जब उसके साथ डिजिटल साक्षरता, सामाजिक नेटवर्क और निर्णयकारी शक्ति का विकास भी हो।

प्रस्तावित मॉडल डिजिटल मीडिया और आदिवासी महिला सशक्तिकरण के संबंध को समझने के लिए एक समग्र समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह मॉडल स्पष्ट करता है कि डिजिटल तकनीक स्वयं सशक्तिकरण उत्पन्न नहीं करती, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और संस्थागत प्रक्रियाओं के माध्यम से महिलाओं की एजेंसी का निर्माण करती है, जो अंततः बहुआयामी सशक्तिकरण का

© 2025 विजय सिंह, डॉ. हितेंद्र सिंह राठौड़. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

आधार बनती है। यह रूपरेखा भविष्य के अनुभवजन्य अध्ययनों तथा नीति-निर्माण के लिए एक उपयोगी विश्लेषणात्मक ढाँचा प्रस्तुत करती है।

चर्चा

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि डिजिटल मीडिया आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सामाजिक संसाधन के रूप में उभर रहा है। डिजिटल तकनीक ने सूचना, शिक्षा, संचार, बाजार और शासन तक पहुँच के नए अवसर प्रदान किए हैं, जिससे आदिवासी महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन की संभावनाएँ बढ़ी हैं। तथापि, इस अध्ययन का प्रमुख निष्कर्ष यह है कि डिजिटल मीडिया को केवल तकनीकी उपकरण के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में समझना आवश्यक है। डिजिटल समावेशन आदिवासी महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों, स्वास्थ्य जागरूकता, शैक्षिक अवसरों और सामाजिक सहभागिता को बढ़ाने में सहायक है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म महिलाओं को स्थानीय सीमाओं से बाहर निकालकर व्यापक सामाजिक नेटवर्क से जोड़ते हैं, जिससे उनकी सामाजिक पूँजी (Social Capital) में वृद्धि होती है। बोरदियू के सामाजिक पूँजी सिद्धांत के संदर्भ में देखा जाए तो डिजिटल नेटवर्क संसाधनों, अवसरों और संस्थागत समर्थन तक पहुँच का माध्यम बनते हैं।

नेटवर्क समाज सिद्धांत के आलोक में डिजिटल मीडिया आदिवासी महिलाओं को सूचना-आधारित समाज का सक्रिय भागीदार बनाता है। वे अब केवल सूचना की उपभोक्ता नहीं रह गई हैं, बल्कि ज्ञान के उत्पादन, प्रसार और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति में भी योगदान दे रही हैं। डिजिटल मंचों पर आदिवासी भाषा, लोक कला, पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत की प्रस्तुति सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को मजबूत करती है।

अध्ययन यह भी दर्शाता है कि डिजिटल सशक्तिकरण का संबंध केवल आर्थिक लाभों तक सीमित नहीं है। अमर्त्य सेन के क्षमता दृष्टिकोण (Capability Approach) के अनुसार डिजिटल तकनीक महिलाओं के विकल्पों और क्षमताओं का विस्तार करती है। डिजिटल शिक्षा, ई-गवर्नेंस सेवाएँ, ऑनलाइन स्वास्थ्य परामर्श और डिजिटल वित्तीय सेवाएँ महिलाओं को अधिक स्वतंत्र और निर्णयक्षम बनाती हैं।

हालाँकि, आलोचनात्मक विश्लेषण से यह भी स्पष्ट हुआ कि डिजिटल मीडिया स्वतः सशक्तिकरण सुनिश्चित नहीं करता। डिजिटल विभाजन, डिजिटल पितृसत्ता, साइबर हिंसा, भाषाई बहिष्करण तथा तकनीकी अवसंरचना की कमी जैसी चुनौतियाँ आदिवासी महिलाओं की डिजिटल भागीदारी को सीमित करती हैं। इंटरसेक्शनैलिटी सिद्धांत के अनुसार आदिवासी महिलाएँ लिंग, जनजातीय पहचान, वर्ग और भौगोलिक स्थिति जैसी अनेक असमानताओं का संयुक्त प्रभाव अनुभव करती हैं। इसलिए डिजिटल पहुँच को सशक्तिकरण का पर्याय नहीं माना जा सकता।

इसी संदर्भ में प्रस्तुत Tribal Digital Agency Framework (TDAF) यह प्रतिपादित करता है कि डिजिटल पहुँच से लेकर बहुआयामी सशक्तिकरण तक की प्रक्रिया कई मध्यवर्ती चरणों—जैसे डिजिटल साक्षरता, डिजिटल सहभागिता, सामाजिक पूँजी निर्माण और एजेंसी विकास—से होकर गुजरती है। यह मॉडल डिजिटल मीडिया को सामाजिक परिवर्तन के एक माध्यम के रूप में समझने का प्रयास करता है और यह दर्शाता है कि वास्तविक सशक्तिकरण तभी संभव है जब डिजिटल संसाधनों के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक समर्थन भी उपलब्ध हो।

निष्कर्ष

यह अध्ययन डिजिटल मीडिया और आदिवासी महिला सशक्तिकरण के अंतर्संबंध का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है तथा इस विषय की एक सैद्धांतिक पुनर्व्याख्या करने का प्रयास करता है। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि डिजिटल मीडिया आदिवासी महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवसर, सामाजिक नेटवर्किंग, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और राजनीतिक सहभागिता के नए द्वार खोल रहा है। डिजिटल तकनीक महिलाओं की सूचना तक पहुँच बढ़ाने, सामाजिक पूँजी का निर्माण करने और निर्णय क्षमता को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

इसके साथ ही अध्ययन यह भी रेखांकित करता है कि डिजिटल सशक्तिकरण एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। केवल इंटरनेट या स्मार्टफोन की उपलब्धता महिलाओं को सशक्त नहीं बनाती। वास्तविक सशक्तिकरण के लिए डिजिटल साक्षरता, संस्थागत सहयोग, सामाजिक स्वीकृति, लैंगिक समानता और सांस्कृतिक समावेशन आवश्यक हैं। यदि इन कारकों की उपेक्षा की जाती है, तो डिजिटल तकनीक नई असमानताओं और बहिष्करण के रूपों को भी जन्म दे सकती है।

अध्ययन का प्रमुख सैद्धांतिक योगदान Tribal Digital Agency Framework (TDAF) का प्रतिपादन है, जो डिजिटल पहुँच से बहुआयामी सशक्तिकरण तक की प्रक्रिया को एक समग्र समाजशास्त्रीय ढाँचे में समझाता है। यह मॉडल दर्शाता है कि डिजिटल मीडिया की वास्तविक शक्ति महिलाओं की एजेंसी, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता के विकास में निहित है।

नीतिगत दृष्टि से यह अध्ययन सुझाव देता है कि आदिवासी क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना के विस्तार के साथ-साथ डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों, स्थानीय भाषाओं में डिजिटल सामग्री, साइबर सुरक्षा जागरूकता तथा महिलाओं की तकनीकी भागीदारी को बढ़ावा देने वाली योजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तभी डिजिटल मीडिया सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और समावेशी विकास का प्रभावी माध्यम बन सकेगा।

अंततः कहा जा सकता है कि डिजिटल मीडिया आदिवासी महिलाओं के लिए केवल संचार का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक पुनर्स्थापन और सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। भविष्य के शोधों में इस प्रस्तावित मॉडल का विभिन्न आदिवासी समुदायों में अनुभवजन्य परीक्षण किया जा सकता है, जिससे डिजिटल सशक्तिकरण की प्रक्रिया को और अधिक गहराई से समझा जा सके।

सन्दर्भ

1. Bandyopadhyay S, Bhattacharyya S, Basak J. Social knowledge management for rural empowerment: bridging the knowledge divide using social technologies. Routledge; 2020. https://doi.org/10.4324/9780429320170

© 2025 विजय सिंह, डॉ. हितेंद्र सिंह राठौड़. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

2. Bourdieu P. The forms of capital. In: Richardson JG, editor. Handbook of theory and research for the sociology of education. Greenwood Press; 1986. p. 241–258.
3. Castells M. The rise of the network society. 2nd ed. Wiley-Blackwell; 2010.
4. Crenshaw K. Demarginalizing the intersection of race and sex: a Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. University of Chicago Legal Forum. 1989;1989(1):139–167.
5. Dixit A, Banday MUL. Problematising the digital gender gap: invoking decoloniality and intersectionality for inclusive policymaking. Gender & Development. 2022;30(2):299–315. https://doi.org/10.1080/13552074.2022.2086605
6. Naveen S, Parida JK, Panda I. Tribal women empowerment through entrepreneurship: evidence from Mayurbhanj District, Odisha. Frontiers in Sociology. 2023;8:1158770. https://doi.org/10.3389/fsoc.2023.1158770
7. Nayak KV, Alam S. The digital divide, gender and education: challenges for tribal youth in rural Jharkhand during Covid-19. Decision. 2022;49(4):425–436. https://doi.org/10.1007/s40622-022-00315-y
8. Pandey P, Zheng Y. Technologies of power in digital inclusion: reimagining politics and participation. Journal of the Association for Information Systems. 2023;24(5):1228–1254. https://doi.org/10.17705/1jais.00838
9. Panda PK. Inclusion and economic empowerment of rural-tribal women in lac value chain and market. Journal of Social and Economic Development. 2017;19(2):283–297. https://doi.org/10.1007/s40847-017-0042-2
10. Sen A. Development as freedom. Oxford University Press; 1999.
11. Sarkar S. Beyond the "digital divide": the "computer girls" of Seelampur. Feminist Media Studies. 2016;16(6):1082–1098. https://doi.org/10.1080/14680777.2016.1169207
12. Sinha S. Gender digital divide in India: impacting women's participation in the labour market. In: Reflecting on India's development: employment, skill and health. Springer; 2018. p. 229–246. https://doi.org/10.1007/978-981-13-1414-8_14
13. United Nations. The Sustainable Development Goals Report 2023. United Nations; 2023. https://unstats.un.org/sdgs/report/2023/
14. United Nations Development Programme. Human development report 2021/2022: uncertain times, unsettled lives. UNDP; 2021. https://hdr.undp.org
15. World Bank. Digital progress and trends report 2023. World Bank; 2023. https://www.worldbank.org
16. World Economic Forum. Global gender gap report 2024. World Economic Forum; 2024. https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2024

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

© 2025 विजय सिंह, डॉ. हितेंद्र सिंह राठौड़. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/